(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अप्रैल, 1992 के "दि स्टेट्समैन" में "नो टेकर फार वेस्टलैंड कोप्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन हेलीकाप्टरों को विश्व-बाजार में बेचने के प्रयास किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन पार्टियों ने इन हेलीकाप्टरों को कितने-कितने मूल्य पर खरीदने की पेशकश की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव-राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्योंकि वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए वित्त व्यवस्था युनाइटेड किंगडम सरकार से एक अनुदान के द्वारा पूरी की गई थी अतः अनुदान की शर्तों के अधीन इन हेलीकाप्टरों के निपटान के लिए उस सरकार की अनुमति अपेक्षित है। वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के निपटान के लिए यू० के० सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान न किया जाना

1689. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस ने अन्य सरकारी उपक्रमों की तरह अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन उपक्रमों से सेवानिवृत्त हुए अनेक कर्मचारियों को दिसम्बर, 1991 के अन्त तक उन्हें देय उनकी भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जो सेवा-निवृत्त हो गए हैं और जिन्हें दिसम्बर, 1991 के अन्त तक उनकी भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं तथा देय भविष्य निधि का भुगतान सामान्यतया कितने समय में कर दिया जाता है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों ने ही अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजनाएं तैयार कर ली हैं।

(ख) और (ग) एअर इंयिया के मामले में भविष्य निधि संबंधी देय राशियों का निपटान अधिवर्षिता के तत्काल पश्चात् किया जाता है तथा इंडियन एयरलाइंस के मामले में अधिवर्षिता की तारीख से तीस दिनों के भीतर किया जाता है। तथापि, ऐसे कुछ मामले हैं जिसमें निगमों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास को कर्मचारियों द्वारा खाली न किया जाना, न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष लंबित अनुशासनिक मामलों में कर्मचारियों का अंतर्ग्रस्त होना और लाभ प्राप्त कार्यालयों का नामांकन किए बिना सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु आदि जैसे मामले हैं, जिनमें भुगतान में देरी हुई है।

31-12-91 की स्थिति के अनुसार, एयर इंडिया में कुल 132 मामले तथा इंडियन एयर-लाइंस में 33 मामले निपटान के लिए लंबित थे।

Setting up of new hotel in Rajasthan during Eight Five Year Plan period

1690. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government propose to open more hotels in Rajasthan during the year 1992-93 and the Eighth Five Year Plan ;

(b) what is the present financial position of each Government hotel in the State